भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3724

दिनांक 11 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

पशुपालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

3724. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से देश में पशुपालकों के लिए एक वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यक्रम आयोजित करने के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस कार्यक्रम में देशभर से भाग लेने वाले पशुपालकों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या देश में वैज्ञानिक प्रजनन को बढ़ावा देने और चारे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कोई पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पशुओं की बीमारियों, टीकाकरण, नस्ल सुधार, ज़ूनोटिक रोग नियंत्रण और स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में पशुपालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ख): जी हाँ। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD), ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान देश में पशुपालकों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से पांच वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और ग्रामीण विकास में पशुपालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए ज्ञान साझा करना, नीतियों के प्रति जागरूकता पैरा करना और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है।

वर्ष 2025-2026 के दौरान निम्नलिखित विषयों पर CSC के माध्यम से आयोजित पांच वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

i. दिनांक 11 जुलाई 2025 को 2000 CSC स्थलों के माध्यम से "पशुधन उत्पादकता में सुधार" विषय पर कार्यक्रम आयोजन किया गया।
ii. दिनांक 23 जुलाई 2025 को 4000 CSC स्थलों के माध्यम से "पशुधन उत्पादकता बढ़ाना" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया
iii. दिनांक 20 अगस्त 2025 को 2000 CSC स्थलों के माध्यम से "पशुधन उत्पादकता बढ़ाना" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

iv. दिनांक 23 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2000 CSC स्थलों के माध्यम से "पशुपालकों के लिए एथनो वेटरनरी मेडिसिन (EVM)" विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

v. दिनांक 5 फरवरी, 2026 को 2500 CSC स्थलों के माध्यम से "पशुपालन और पशु कल्याण जागरूकता माह" का आयोजन किया गया।

(ग) वर्ष 2025-2026 के दौरान देश भर में 12,500 CSC केंद्रों के ज़रिए आयोजित पाँच वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रमों में कुल 6,41,250 पशुपालकों ने भाग लिया। पांच वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रमों में पशुपालकों की भागीदारी का राज्य-वार विवरण तालिका 1 से 5 में संलग्न है।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग निम्नलिखित योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से प्रजनन को बढ़ावा देने और चारे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) की सहायता कर रहा है:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** वैज्ञानिक रूप से प्रजनन को बढ़ावा देने में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग करने के लिए, भारत सरकार (GOI) का पशुपालन और डेयरी विभाग, दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) का कार्यान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य देशी नस्लों का विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी का आनुवंशिक उन्नयन और दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है ताकि किसानों के लिए दूध उत्पादन अधिक लाभकारी हो सके।

2. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** देश में वैज्ञानिक प्रजनन को बढ़ावा देने और चारे की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, वित्तीय वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना है और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मांस, बकरी के दूध, अंडे और ऊन का उत्पादन बढ़ाना है। NLM योजना की मूल अवधारणा उद्यमियों का विकास करना है ताकि असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उत्पाद हेतु उत्पादन पूर्व और उत्पादनोत्तर सुविधाओं (Forword and backword linkages) का निर्माण किया जा सके और इसे संगठित क्षेत्र से जोड़ा जा सके।

   राष्ट्रीय पशुधन मिशन के पशुधन और पोल्ट्री नस्ल विकास संबंधी उप-मिशन का उद्देश्य नस्ल संरक्षण और नस्ल सुधार अवसंरचना की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, गधा, घोड़ा और खच्चर के आनुवंशिक नस्ल सुधार पर विशेष रूप से ध्यान देना है।

   पशु आहार और चारा विकास संबंधी उप मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग का उद्देश्य चारा उत्पादन के लिए अपेक्षित प्रमाणित चारा बीजों की उपलब्धता में सुधार करने और प्रोत्साहन के माध्यम से चारा ब्लॉक/हे बेलिंग/साइलेज निर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए चारा बीज श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण करना है।

(ङ) पशुपालकों के बीच पशुधन रोगों, टीकाकरण, नस्ल सुधार, ज़ूनोटिक रोग नियंत्रण और स्वच्छता पद्धतियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग और सहायता करने हेतु, विभाग ने जागरूकता सृजन को विभिन्न योजनाओं का अभिन्न अंग बना दिया है। इनका विवरण निम्नानुसार है:

i. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत,** देशी बोवाइन नस्लों के महत्व के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ा-बछड़ी रैलियों, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनार और कार्यशालाएं, सम्मेलनों आदि का आयोजन किया गया है।

ii. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम** (LHDCP) योजना के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पशुपालन की बेहतर पद्धतियों, जैव सुरक्षा/स्वच्छता उपायों, पशु रोगों के लिए टीकाकरण, रोग निगरानी और मॉनीटरिंग तथा क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता में सहायता करती है।

iii. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत,** पशुधन किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग, नवाचार और विस्तार संबंधी उप मिशन के अंतर्गत पशुपालन और योजनाओं के

लिए प्रचार कार्यकलापों, सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रदर्शन कार्यकलापों और जागरूकता सृजन हेतु अन्य सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) कार्यकलापों सहित विस्तार सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग, द्वारा आधुनिक पशुपालन पद्धतियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और देश भर में पशुधन के कल्याण में सुधार के उद्देश्य से प्रति वर्ष 14 जनवरी से 13 फरवरी तक "पशुपालन और पशु कल्याण जागरूकता माह" मनाया जाता है।

iv. पशुपालन और डेयरी विभाग ने रोग मुक्त पोल्ट्री कक्षों की स्थापना और रखरखाव के लिए राज्य पशु चिकित्सा सेवाओं, अनुसंधान संस्थानों, पोल्ट्री उद्योग और किसानों के बीच क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु दिनांक 8 मई 2026 को हैदराबाद में "मुर्गी पालन रोग मुक्त कंपार्टमेंट: विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) फ्रेमवर्क और भारतीय परिप्रेक्ष्य" संबंधी राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। **"**मास्टिटिस जागरूकता माह - जून 2026" अभियान भी आयोजित किया गया, जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्थानीय भाषाओं में किसान जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शन और IEC प्रसार का आयोजन किया, जिससे पशुधन स्वास्थ्य जागरूकता, रोग नियंत्रण और स्वच्छ दूध उत्पादन का सुदृढ़ीकरण किया गया।

v. उपर्युक्त के अलावा, विभाग प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), प्रसार भारती और केंद्रीय संचार ब्यूरो जैसी एजेंसियों के सहयोग से, मीडिया और सोशल अभियान चलाकर, प्रदर्शनियां आयोजित करके, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, पशु मेलों का आयोजन करके और विस्तार सेवाओं में राज्य सरकारों की सहायता करके पशुपालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए पहुंच का विस्तार करता है। टीकाकरण अभियानों के दौरान, विभाग यूट्यूब और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर टीवी और रेडियो स्पॉट प्रसारित करता है। विभाग पशुधन स्वास्थ्य, टीकाकरण, नस्ल सुधार, ज़ूनोटिक रोग नियंत्रण और स्वच्छता प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पुस्तिकाएं और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) जैसी IEC सामग्री तैयार और वितरित करता है।

vi. इसके अलावा, विभाग द्वारा देशी पशुओं को पालने वाले किसान, AI तकनीशियनों और डेयरी सहकारी समितियों/दूध उत्पादक कंपनियों/पशुधन क्षेत्र में कार्य करने वाले डेयरी किसानों उत्पादक संगठनों जैसे सभी व्यक्तियों को चिन्हित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, प्रति वर्ष राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है।

****

अनुबंध

तालिका 1: दिनांक 11 जुलाई, 2025 को सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से आयोजित वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले पशुपालकों का राज्य-वार विवरण

क्र .सं.	राज्य	भाग लेने वाले पशुपालकों की संख्या
1	गुजरात	14,700
2	महाराष्ट्र	18,200
3	राजस्थान	16,400
4	कर्नाटक	12,000
5	आंध्र प्रदेश	17,800
6	तमिलनाडु	8,800
7	तेलंगाना	8,000
8	पुदुचेरी	2,000
9	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,600
10	गोवा	1,500
कुल		**1,02,000**

तालिका 2: दिनांक 23 जुलाई, 2025 को सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से आयोजित वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले पशुपालकों का राज्य-वार विवरण

क्र .सं.	राज्य	भाग लेने वाले पशुपालकों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	2,400
2	असम	14,300
3	बिहार	45,800
4	हरियाणा	21,300
5	हिमाचल प्रदेश	8,100
6	जम्मू और कश्मीर	12,500
7	लद्दाख	2,900
8	मणिपुर	5,100
9	मेघालय	2,400
10	मिजोरम	5,000
11	नागालैंड	5,000
12	पंजाब	11,700
13	सिक्किम	4,600
14	त्रिपुरा	3,500
15	उत्तर प्रदेश	50,300
16	उत्तराखंड	9,800
कुल		**2,04,700**

तालिका 3: दिनांक 20 अगस्त, 2025 को सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से आयोजित वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले पशुपालकों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	भाग लेने वाले पशुपालकों की संख्या
1	ओडिशा	25,000
2	चंडीगढ़	800
3	छत्तीसगढ़	13,050
4	दिल्ली	3,200
5	झारखंड	14,400
6	केरल	1,900
7	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	500
8	मध्य प्रदेश	22,100
9	पश्चिम बंगाल	22,200
कुल		**1,03,150**

तालिका 4: दिनांक 23 सितंबर, 2025 को सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से आयोजित वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले पशुपालकों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	भाग लेने वाले पशुपालकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	5,900
2	बिहार	6,850
3	छत्तीसगढ़	7,900
4	गुजरात	7,200
5	हरियाणा	7,100
6	हरियाणा	350
7	हिमाचल प्रदेश	1,050
8	जम्मू और कश्मीर	2,600
9	झारखंड	3,500
10	कर्नाटक	5,550
11	केरल	1,550
12	मध्य प्रदेश	6,250
13	महाराष्ट्र	7,450
14	नागालैंड	500
15	ओडिशा	6,350
16	पुदुचेरी	500
17	पंजाब	3,550
18	राजस्थान	7,600
19	तमिलनाडु	2,950
20	तेलंगाना	3,550
21	उत्तर प्रदेश	7,450
22	उत्तराखंड	5,600
23	पश्चिम बंगाल	2,800
कुल		**1,04,100**

तालिका 5: दिनांक 05 फरवरी, 2026 को आयोजित सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले पशुपालकों का राज्य-वार विवरण

क्र .सं.	**राज्य**	**भाग लेने वाले पशुपालकों की संख्या**
1	उत्तर प्रदेश	10,600
2	महाराष्ट्र	9,400
3	गुजरात	8,550
4	छत्तीसगढ़	7,800
5	उत्तराखंड	7,500
6	पश्चिम बंगाल	7,500
7	ओडिशा	7,450
8	हरियाणा	7,200
9	राजस्थान	6,700
10	बिहार	6,650
11	आंध्र प्रदेश	6,500
12	पंजाब	6,500
13	कर्नाटक	5,800
14	मध्य प्रदेश	5,300
15	तमिलनाडु	5,050
16	असम	3,000
17	झारखंड	2,700
18	जम्मू और कश्मीर	2,500
19	त्रिपुरा	2,300
20	हिमाचल प्रदेश	1,900
21	दिल्ली	1,500
22	सिक्किम	1,500
23	केरल	950
24	मेघालय	550
25	मणिपुर	500
26	मिजोरम	500
27	पुदुचेरी	500
28	अरुणाचल प्रदेश	400
	कुल योग	**1,27,300**